

प्रेषक,
हरिश्चन्द्र जोशी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,
समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग-1

देहरादून दिनांक: 19 जनवरी, 2007

विषय: दैनिक समाचार पत्र 'अमर उजाला' में प्रकाशित खबर "बारूद के ढेर में बैठी है उत्तराखण्ड की राजधानी"।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 964/XIX/06-87/2006, दिनांक: 04 अगस्त, 2006 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा एल0पी0जी0 गैस गोदामों को अन्यत्र सुरक्षित स्थानों में स्थानान्तरित करने के निर्देश दिये गये थे।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एल0पी0जी0 गैस की भारत सरकार द्वारा सखिडाईज दरों पर आपूर्ति की जाती है। जिसका डाईवर्जन होने पर जनपदों में बड़े पैमाने पर आपूर्ति बाधित होती है। ऐसी दशा में सरकार की छवि धुमिल होने के साथ-साथ जनसामान्य पर भी व्यापक असर पड़ता है।
3. प्रश्नगत मामले में अपने-अपने जनपदों में संचालित हो रहे समस्त गैस गोदामों का तत्काल निरीक्षण कर यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन गैस एजेन्सियों के गोदामों तथा विक्रय केंद्रों पर सुरक्षा के सभी उपाय किये जा रहे हैं अथवा नहीं। जिन एजेन्सियों द्वारा सुरक्षा के उपायों में ढील दृष्टी जा रही है उनके विरुद्ध सुसंगत नियमों के अनुकूल कार्यवाही की जाय।
4. गैस एजेन्सियों के संबंध में यह भी देख लिया जाय कि घनी आबादी में स्थित गैस एजेन्सियों के गोदामों से अथवा अन्यथा आबादी को खतरा होने की सम्भावना तो नहीं है। यदि कहीं पर ऐसी स्थिति परिलक्षित होती है तो ऐसे गोदामों को अन्यत्र सुरक्षित स्थानों में स्थानान्तरित करने की कार्यवाही योजनाबद्ध तरीके से की जाय।
5. शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाये गये हैं कि एल0पी0जी0 गैस के अवैध रिफिलिंग (बड़े सिलेण्डरों से छोटे सिलेण्डरों में गैस भण्डारण) बड़ी मात्रा में किया जा रहा है। यदि किसी एल0पी0जी0 गैस गोदामों में अथवा किसी व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से सिलेण्डरों का भण्डारण तो नहीं किया गया है। यदि ऐसे प्रकरण पकड़ में आते हैं तो तुरन्त दण्डात्मक कार्यवाही की जाय। जिसमें गैस एजेन्सियों के निरीक्षण के लिए गठित टीमों में संबंधित तेल कम्पनी के प्रतिनिधियों को भी सम्मिलित कर कार्यवाही की जाय।

अतः अनुरोध है कि अपने-अपने जनपदों में उपर्युक्त निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें। प्रश्नगत प्रकरण में मा0मुख्यमंत्री द्वारा समीक्षा की जा रही है। कृपया आपका व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है।

भवदीय,
(हरिश्चन्द्र जोशी)
सचिव।

संख्या: 79 (1)/XIX/2007, तदुद्दिष्ट।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. आयुक्त, कुमायूँ/गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
2. आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
4. सहायक आयुक्त, खाद्य कुमायूँ/गढ़वाल संभाग।
5. नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग, उत्तराखण्ड।
6. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड।
7. समस्त जिलापूर्ति अधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. सैल्स/एरिया मैनेजर, एलपीजी गैस कम्पनी, आईओसी/बीपीसी/एचपीसी तथा आईबीपी उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि विभिन्न जनपदों में गैस एजेंसियों के निरीक्षण के लिए गठित टीमों को अपेक्षित सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।
9. निजी सचिव, माओ मंत्री जी खाद्य विभाग, देहरादून।
10. सचिव, एनआईसी सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(हरिश्चन्द्र जोशी)
सचिव।